नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

जजों की संख्या निचली अदालतों में बढ़नी चाहिए

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का हाल ही में लिया गया फैसला निश्चित रूप से स्वागतयोग्य है, लेकिन इसे न्याय व्यवस्था की सारी समस्याओं का समाधान मान लेना जल्दबाजी होगी. संसद ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान किया है. इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी. यह वृद्धि ऐसे समय हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में करीब 92 हजार मामले लंबित हैं. जाहिर है, अतिरिक्त न्यायाधीशों से अदालत पर काम का बोझ कुछ कम होगा और अधिक पीठों के गठन से मामलों की सुनवाई की गति बढ़ेगी.

इसका एक महत्वपूर्ण लाभ संविधान पीठों के गठन में भी मिल सकता है. पांच, सात या नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठों के सामने लंबित संवैधानिक प्रश्नों का शीघ्र निपटारा होने से कानून की व्याख्या स्पष्ट होगी और देशभर की अदालतों को दिशा मिलेगी. कई महत्वपूर्ण मुद्दे केवल इसलिए लंबित रहते हैं क्योंकि संविधान पीठ के गठन के लिए पर्याप्त न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते. अतिरिक्त न्यायाधीश इस स्थिति को बदल सकते हैं. लेकिन न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी सुप्रीम कोर्ट में नहीं, बल्कि अदालतों की पूरी श्रृंखला में फैली हुई है. उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में लंबित मामलों की संख्या कहीं अधिक है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के उच्च न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं. जिला अदालतों में स्थिति और गंभीर है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में चार जज बढ़ा देने भर से न्याय पाने की राह आसान नहीं हो जाएगी.

वास्तविकता यह है कि देश के अधिकांश नागरिकों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना आसान नहीं है. आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति ही लंबे मुकदमे की लागत, दिल्ली तक आने-जाने और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फीस का भार उठा सकता है. गरीब और मध्यमवर्गीय व्यक्ति के लिए न्याय की पहली और अंतिम उम्मीद स्थानीय अदालत ही होती है. इसलिए न्यायिक सुधार की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए.

उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं. जिला अदालतों में भी न्यायाधीशों और न्यायिक कर्मचारियों की कमी है. अदालतों का बुनियादी ढांचा कई जगह अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है. इसके अलावा अनावश्यक स्थगन यानी तारीख पर तारीख की संस्कृति ने न्याय प्रक्रिया को धीमा कर रखा है. इन कमियों को दूर किए बिना केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना समग्र हल नहीं है. जरूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों में भी न्यायाधीशों के रिक्त पद तत्काल भरे जाएं. ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और केस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी बनाया जाए. अनावश्यक स्थगन पर अंकुश लगे और मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था मजबूत हो. न्यायाधीशों के साथ पर्याप्त न्यायिक कर्मचारी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है.

दरअसल, न्याय की असली नींव जिला अदालतों में है. न्याय तब सार्थक होगा जब नागरिक को वर्षों इंतजार, भारी खर्च और तारीखों के अंतहीन सिलसिले से गुजरना न पड़े. जजों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है ऐसी न्याय व्यवस्था बनाना जिसमें न्याय जल्दी मिले, सुलभ हो और आम आदमी की पहुंच में हो.

पारदर्शी सरकारी खरीद का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जेम

पीयूष गोयल

> जेमपोर्टल भारत की आर्थिक वृद्धि और पीएम मोदी के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में कार्यरत है. यह समाज के वंचित वाले वर्गों को सशक्त बनाता और उनका उत्थान करता है तथा उद्यमिता को बढ़ावा देता है. साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स देने वालों का पैसा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को कुशलतापूर्वक खरीदने में इस्तेमाल हो.

सरकारी खरीद के लिए सरकार का ई-मार्केटप्लेस (जेम) वैश्विक स्तर पर एक पारदर्शी, समावेशी और कुशल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जो 1.37 लाख सरकारी खरीदारों को 25 लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है. जेम प्लेटफार्म की विशेषता है कि यह खरीद से जुड़ी सभी प्रमुख गतिविधियों को एक बड़े डिजिटल मार्केटप्लेस में एकीकृत करता है. यह वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों को सरकार के समावेशी विकास के साथ जोड़ता है, जिससे यह पीएम मोदी के विकासित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन जाता है.

2016 में पीएम द्वारा इस परिवर्तनकारी डिजिटल पहल की शुरुआत के एक दशक में, जेम ने भ्रष्टाचार को मिटाकर और स्टार्टअप, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और छोटे शहरों के व्यवसायों को बढ़ावा देकर, सरकारी खरीद में क्रांति ला दी है. उपयोगकर्ता-अनुकूल यह प्लेटफ़ॉर्म वास्तव में एक रत्न है, जिसने विवादित आपूर्ति और निपटान महानिदेशालयकी जगह ली है, जिसकी प्रणालियाँ अस्पष्ट और गैर-प्रतिस्पर्धी थीं. इससे खरीदारी प्रणाली के केवल कुछ सुविधा-प्राप्त लोगों को ही अनुचित फ़ायदा मिलता था.

यह उचित है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया, आधुनिक कार्यालय, वाणिज्य भवन, उसी ज़मीन पर बना है, जहाँ कभी वह पुरानी और संदिग्ध प्रतिष्ठा वाली संस्था हुआ करती थी. वाणिज्य और उद्योग के मंत्री के रूप में, मुझे गर्व है कि जेम, जिसे 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, अपनी शानदार सेवा के दस साल पूरे कर रहा है. यह सिर्फ आंकड़ों का जश्न मनाने वाला पड़ाव नहीं है; बल्कि यह इस बात में एक बुनियादी और सफल बदलाव है कि कैसे सरकारी खरीद देश के निर्माण में योगदान देती है.

उत्पाद खोजने और बोली लगाने से लेकर अनुबंध देने और भुगतान करने तक, पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर जेम ने मनमाने फैसलों को खत्म किया है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है और लोगों के भरोसे को मजबूत किया है. हर लेन-देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है जिसकी जांच की जा सकती है; इससे जवाबदेही बढ़ती है और सरकारी खरीद के प्रति निष्ठा मजबूत होती है. जेम पीएम मोदी के व्यवसाय करने में आसानी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. एकल डिजिटल विंडो, आसान पंजीकरण, मानकीकृत प्रक्रिया और नियमित नीतिगत सुधार - जैसे अमानत राशि को ख़त्म करना और लेन-देन शुल्क को युक्तिसंगत बनाना - के जरिये जेम ने भागीदार बनने की बाधाओं को काफी हद तक कम किया है, जिससे सरकारी खरीद तक पहुंच आसान हो गयी है. जेम ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लक्ष्य को मजबूती से आगे बढ़ाया है. घरेलू निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता देकर, इसने स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत किया है और देशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया है.

पोर्टल पर दिया गया हर ऑर्डर भारत की निर्माण क्षमता और आर्थिक संप्रभुता में एक निवेश है. खास बात यह है कि जेम में मात्रा के आधार पर लगभग 60% ऑर्डर और सकल माल मूल्य (जीएमवी) में 45% से ज़्यादा की हिस्सेदारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की है. जेम, पीएम मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' मिशन के अनुरूप समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में सेवाएं देता है. यह स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसायों और महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बिना किसी बाधा या मध्यस्थ केसरकारी खरीदारों के सामने अपने उत्पादों और सेवाओं को आसान तरीके से पेश करने का मौका देता है. प्रवेश करने की बाधाओं को खत्म करके और सरकारी खरीद तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाकर, जेम ने पूरे देश के छोटे व्यवसायों को राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने और उस व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सशक्त बनाया है, जिस पर कभी स्थापित कंपनियों का दबदबा हुआ करता था.

जेम के माध्यम से 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी ऑर्डर पूरे किए हैं. 2.20 लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों ने 99,713 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर हासिल किए हैं, जबकि 42,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 65,600 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं. जेम ने 69,000 से ज्यादा एससी/एसटी उद्यमियों को सरकारी खरीद में भाग लेने का अवसर दिया है, और उन्होंने 23,145 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं.

(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं)

डिजिटल पेमेंट पर शुल्क संभव

आजकल लोग मनीपर्स में ज्यादा नकद रकम नहीं रखते, क्योंकि छोटे मोटे खर्च के लिए यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) से डिजिटल भुगतान करना आम बात हो गई है. यह आसान उपयुक्त व लोकप्रिय प्रणाली है. इसके बावजूद अब इसके सामने दिक्कत आने के आसार हैं. गत सप्ताह इस आर्थिक व्यवहार पर लोकसभा में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू करने का प्रस्ताव पारित हो गया. अब यह विधेयक राज्यसभा में जाएगा और वहां पास होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश में यह कानून लागू हो जाएगा. सरकार इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी कि यह शुल्क किस पर लागू होगा और उसकी दर क्या रहेगी.

कहा जा रहा है कि 2,000 रुपये से अधिक के लेन-देन पर यह शुल्क लगाया जाएगा. यदि व्यापारियों पर यह शुल्क लागू किया गया, तो वह ग्राहकों से इसकी वसूली करेंगे. पहले ही हर वस्तु व सेवा पर जीएसटी लागू है, ऊपर से यह एमडीआर भी देना पड़ेगा. इससे जनता पर बोझ आएगा, तो फिर लोग यूपीआई पेमेंट की बजाय वापस नगदी भुगतान पर लौट आएंगे. अभी सुविधा यह है कि मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करो, रकम एंटर करो तो एक क्लिक में भुगतान हो जाता है. सरकार की दलील है कि यूपीआई मुफ्त रहने से सर्वर, साइबर सुरक्षा, व्यवहार के सेटलमेंट, तकनीकी देखभाल पर बड़ा खर्च आता है. यह सारा खर्च सरकार उठाती है. दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि यूपीआई की वजह से नकद लेन-देन में कमी आने से रिजर्व बैंक को अधिक तादाद में नोट छापने नहीं पड़ते. यह भी तो एक तरह से सरकारी खर्च में बचत है. सरकार को यह भी फायदा है कि यूपीआई की वजह से बड़े पैमाने पर व्यवहार आयकर रिटर्न में दिखाया जाने लगा है. यूपीआई सिर्फ भुगतान प्रणाली न होकर अर्थव्यवस्था का आधार बनती जा रही है. अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, ब्राजील जैसे अनेक देशों में इस तरह का डिजिटल पेमेंट निशुल्क है, लेकिन व्यापारी कुछ सेवा शुल्क वसूल करते हैं. केवल भारत में यूपीआई डिजिटल लेन-देन मुफ्त है. इतना अवश्य है कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 1 या 2 प्रतिशत एमडीआर भरना पड़ता है जिससे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, बैंक व सेवा कंपनियों को आय होती है.

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

दिल्ली डायरी

अपने-अपने कुनबे को बचाए रखने की जद्दोजहद

प्रवेश कुमार मिश्र

संसद का मानसून सत्र वैसे तो अब अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है लेकिन बाकी बचे दो दिन भी विपक्षी कुनबे के लिए भारी पड़ रहा है. चर्चा है कि सरकार अंतिम समय में अपनी महत्वाकांक्षी विधेयकों में से एक परिसीमन विधेयक व महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पुन: पेश करते हुए इसे पास कराने की कोशिश करेगी. संभवत: इसी वजह से इंडिया गठबंधन में शामिल दल जो उक्त विधेयक का लगातार विरोध करते रहे हैं उन्हें अब यह भय सताने लगा है कि कहीं टीएमसी व शिवसेना उद्धव गुट के तर्ज पर उनके एकजुटता में सेंधमारी न हो जाए.

चर्चा है कि सत्ता पक्ष के रणनीतिक व व्यवहारिक दबाव में विरोधी समूह के कुछ सांसद या तो पार्टी विप के खिलाफ जाकर विधेयक के पक्ष में वोट कर देंगे या वोटिंग के समय सदन में अनुपस्थित हो जाएंगे. इन दोनों परिस्थितियों में विधेयक बहुमत के आधार पर लोकसभा में पारित हो सकता है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि खास तौर पर सपा, डीएमके ,एनसीपी शरद गुट, राजद, कुछ कथित तौर पर उपेक्षित कांग्रेसी सांसद वोटिंग के समय कोई अप्रत्याशित खेल कर सकते हैं. संभवत: इसी वजह से सपा में छोटे छोटे समूहों में सांसदों की टीम बनाकर उनपर नजर रखते हुए अपने अपने कुनबे को बचाए रखने की कोशिश में लगे हैं.

सदन के अंदर व बाहर आमने-सामने का विरोध

वैसे तो आरंभिक दिनों से ही संसद का मानसून सत्र विपक्षी दलों के विरोध के कारण हंगामेदार रहा है लेकिन पिछले कुछ दिनों से संसद के गलियारों में कुछ अलग तरह की गहमागहमी दिख रही है. वॉकआउट और नारेबाजी के बीच दोनों सदनों में एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच संसद भवन परिसर में जिस तरह से पक्ष व विपक्ष के सदस्य तख्तियों के सहारे अलग-अलग नारों के साथ विरोध कर रहे हैं वह अजूबा है. पहले विरोधी दल के लोग सत्ता पक्ष का विरोध करते थे लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग भी तख्तियों के साथ मार्च करते हुए विपक्षी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे. अब तो सत्ता पक्ष के सांसद हों या विपक्षी सांसदों ने एक दूसरे के विरोधी खेमे के वरिष्ठ नेताओं को सीधे रोक कर सवाल पूछने की प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं.

राहुल गांधी के युवा संवाद की सफलता से राजग खेमे में बेचैनी

राहुल गांधी का इलाहाबाद में आयोजित छात्रों के साथ संवाद नेशनल मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर छाया रहा. जिस तरह से राहुल ने युवाओं के रोजगार, शिक्षा प्रणाली और भविष्य की चिंताओं पर सीधी बात करते हुए बिना किसी बनावट के, युवाओं के तीखे सवालों पर उनको बेबाक जवाब दिया , उसने इस संवाद को बेहद जीवंत बना दिया. कांग्रेसी रणनीतिकार इस अभियान को भविष्य का रोड मैप मानते हुए पार्टी के प्रति युवाओं के बढ़ते विश्वास का आधार मान रहे हैं. जबकि इस अभियान के कथित सफलता ने राजग खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है. राजग खेमे को चिंता है कि जेन जी व जेन अल्फा जिस तरह से इस अभियान को सफल बना रहा है वह यदि वोट में तब्दील हो गया तो भविष्य की राजनीति आसान नहीं रहेगी.

सॉफ्ट हिन्दुत्व की ओर सपाईयों का बढ़ता कदम

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व और पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के संग पंडितों को जोड़कर नया दांव चला है. अखिलेश यादव ने 10 साल बनाम 5 साल का नारा देकर आक्रामक रथ यात्रा की जमीन तैयार कर ली है. सपा रणनीतिकारों की बदलती रणनीति ने जहां एक तरफ भाजपा को परेशान किया है वहीं दूसरी ओर बसपा भी बेचैन हो गई है.

शरद पवार के अस्पष्ट रूख से इंडिया गठबंधन में बेचैनी

विपक्षी समूह का हिस्सा होने के बावजूद शरद पवार की पार्टी के सांसदों ने पिछले दिनों अचानक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सीधे मुलाकात कर ली. इसे मुलाकात को भले ही वे क्षेत्र की समस्याओं से जोड़ रहे हों, लेकिन उनकी इस सुलह और दबाव वाली नीति ने करीबियों और विरोधियों दोनों को उलझा रखा है. कांग्रेस के लोग वैसे तो इस विषय पर खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे हैं लेकिन शरद पवार की गुगली राजनीति से सशंकित जरूर हैं. हालांकि सत्ता पक्ष के लोग इस राजनीतिक मिलन को भविष्य की राजनीति से जोड़कर कह रहे हैं कि मराठा नेता खुलेआम अपनी भावीं रणनीति को स्पष्टता के साथ रेखांकित कर रहे हैं लेकिन जो नहीं समझ रहा है वह परिस्थिति को झूठला रहा है.

निशानेबाज

तोड़ा अहिंसा के पुजारी का विश्वास आ गए डुप्लीकेट मोहनदास

पड़ोसी ने हमसे कहा, 'निशानेबाज, यह मत समझिए कि हर चमकती चीज सोना होती है! अंग्रेजी में कहते हैं- ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. विश्ववंदनीय बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन अब आरएसएस में भी एक मोहनदास पैदा हो गए हैं जो हिंसा के जबरदस्त हिमायती हैं. संघ के विचारक टी.जी. मोहनदास ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं के बारे में जहर उगलते हुए कहा था कि अगर हालात संभालने की जिम्मेदारी उनके पास होती, तो वह जंतर-मंतर के आसपास 4 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगाते फिर प्रदर्शनकारियों को 3 बार हटने की चेतावनी देने के बाद उन पर गोलियां चलवाते. कुछ की मौत हो जाती, कुछ घायल हो जाते. शवों को अस्पताल ले जाया जाता और 4 घंटे के भीतर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाता.'

हमने कहा, 'संघ के इस मोहनदास को चीन या उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही देश में भेज देना चाहिए. वहां ऐसे

वीभत्स सोचवाले इस हिंसक आदमी को शी जिनपिंग या किम जोंग अपना स्पेशल असिस्टेंट बना लेंगे. संघ का विचारक कहलाने वाले टी.जी. मोहनदास के तानाशाही विचारों का संघ प्रमुख ने अब तक खंडन नहीं किया? क्या उन्होंने इसे मौन सहमति दी है? क्या यही इस संगठन की असली विचारधारा है.'

पड़ोसी ने कहा, 'निशानेबाज, मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों के विपरीत वर्तमान स्थिति देखी जा रही है. अहिंसा की जगह हिंसा, संयम की बजाय व्यभिचार, अपरिग्रह की बजाय चंदाचोरी. नेताओं के पास सैकड़ों की दौलत, ऐसा केयर फंड जिसके बारे में पूछना मना है, जिसके बल पर पार्टियां तोड़ी जाती हैं और सांसद-विधायक खरीदे जाते हैं.'

हमने कहा, 'सदाचार की बजाय भ्रष्टाचार आ गया. मेक इन इंडिया सिर्फ नारा बनकर रह गया. गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, लेकिन अब उसी ब्रिटेन से व्यापार समझौता कर मैनचेस्टर के कपड़े और ब्रिटेन में निर्मित व्हिस्की भारत मंगवाई जा रही है. बापू की सादगी की बजाय भड़कीलापन बढ़ता जा रहा है. शीर्ष नेता बहुरुपिए के समान बार-बार अपना परिधान बदलते हैं. मराठी में इसे सोंगाड्या कहते हैं. महात्मा गांधी की खादी फैशन शो में चली गई है. गांव अपनी बदनसीबी पर रो रहे हैं और शहर चमकदार होते जा रहे हैं. असली मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीर सिर्फ नोटों पर रह गई है, जो बीयरबार से लेकर कोठों तक जा रहे हैं. दूसरी ओर हिंसा के समर्थक टी.जी. मोहनदास संघ के महान विचारक कहला रहे हैं.'

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12347 - डॉ. सागर खादीवाला

आधार पर कोई वस्तु कहीं पहुंचाई जाती हो 3. पुरुष, मर्द, पुरुष जाति का 4. आग या उसके सामने रखकर गर्मी पहुंचाना 6. घायल, दुखी, चोट खाया हुआ 8. किसी तरल पदार्थ को लकड़ी-रई आदि से बिलोना 10. चप्पल, पादुका (सं.) 12. जिससे, इसलिए कि 14. साफ करना, परिमार्जित करना 15. जरा, थोड़ा, अल्प 16. लड़ाई-झगड़ा, हाथापायी, शारीरिक चोट पहुंचाना 17. तीक्ष्ण, पैना, धारदार 20. दही से बना पेय पदार्थ 21. अगर, जो

बाएं से दाएं
1. खंडहर (सं.) अग्नि 4. चोरी करने के लिए दीवार तोड़कर बनाया हुआ छेद, नकब, सुरंग 5. महादेव, प्रत्येक 6. मदार, अकबन 7. पुष्प, कुसुम 9. बहन का संबंध 11. शतरंज का एक मोहरा जिसे ऊंट कहते है 13. नामजद, प्रसिद्ध 16. मिकदार, परिणाम 18. हटाना, दूर करना 19. फिल्म-नाटक आदि में दुष्ट पात्र की भूमिका करने वाला 22. डोरी, रज्जु 23. कांटा, विघ्न

ऊपर से नीचे
1. बक नाम का दैत्य जो कृष्ण के हाथों मारा गया (सं.) 2. सवारी, वह जिसके द्वारा

Solution 12346

घों		द	र	वा	जा		
स		र	ज	त	प	ट	
ला	य	क			क	मा	न
	था	ना		ढ		ट	स
अ	र्थ		ल	ल	का	र	ना
पा		उ	प	ना	म		
हि	सा	ब			का	बि	ल
ज		रा	स्ता		जी	ना	

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में योजनाओं का शुभारंभ होगा. सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी. वर्ष के मध्य में पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा. व्यवसाय में सुधार होगा. वर्ष के अन्त में उतावलेपन में लिये गये निर्णय से हानि होगी. शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा. अत्याधिक परिश्रम से मन व्यथित रहेगा.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को शत्रु पक्ष प्रबल होगा. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को अत्याधिक परिश्रम से मन में पीड़ा होगी, और थकान महसूस करेंगे. कर्क राशि के व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को व्यापार में सुधार होगा. सिंह राशि के व्यकितयों को यथेष्ठ संयम से काम लेना हितकर रहेगा. अपनी वाक पटुता पर विशेष संयम रखना चाहिये.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक हंसमुख, मिलनसार होगा. खेलकूद के प्रति रूचि रहेगी. बचपन में स्वास्थ्य पीड़ा होगी. बाद में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. माता पिता का भक्त होगा. मनोवांछित सफलता मिलेगी.

उदयकालीन ग्रह चाल

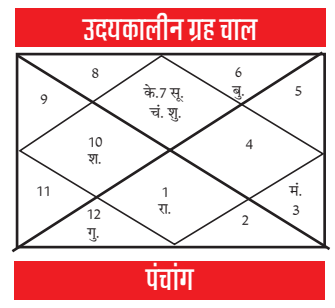

पंचांग

रा.मि. 21 संवत् 2083 श्रावण कृष्ण अमावस्या बुधवासरे रात 11/14, पुष्य नक्षत्रे दिन 8/42, व्यतिपात योगे शाम 5/15, चतुष्पद करणे सू.उ. 5/30, सू.अ. 6/30, चन्द्रचार कर्क, पर्व- स्नानदान श्राद्ध अमावस्या, हरियाली अमावस्या, शु.रा. 4,6,7,10,11,2 अ.रा. 5,8,9,12,1,3 शुभांक- 6,8,2.

व्यापार भविष्य

श्रावण कृष्ण अमावस्या को पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से गेहू, जौ, चना, गुड़ खांड़, शक्कर मूँगफली तेलों में तेजी होगी. वायदा विचार आज 2 बजकर 11 मिनिट से 10 मिनिट के रूख पर व्यापार करके लाभ उठाना हितकर रहेगा. भाग्यांक 1583 है.

मेष- जीवनसाथी के व्यवहार से खिन्नता रहेगी. मांगलिक खर्च की रूपरेखा बनेगी. मित्रों एवं कुटुम्बियों से सहयोग मिलेगा. मानसिक संतोष रहेगा.

वृषभ- प्रियजन से मुलाकात उपयोगी रहेगी. ले देकर काम करवाने में नुकसान होगा. भ्रमण मनोरंजन एवं आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी. प्रयत्न करने पर लाभ होगा.

मिथुन- प्रापर्टी को लेकर चल रहे विवाद उभर सकते है. कोई पुराना काम बनेगा. दूर दराज की यात्राओं का योग है. सफ्लता प्राप्त होगी. रूका धन प्राप्त हो सकता है.

कर्क- अटके कार्य को समेटने में सफ्लता मिलेगी. कानूनी मामले सुलझेंगे. प्रयत्न करने पर लाभ होगा. निजी कार्यो की रूपरेखा तैयार होगी.

सिंह- अनुशासन की कमी से कार्यस्थल पर अव्यवस्था हो सकती है, लेनदेन के मामले सुलझ जायेंगे. पूज्य व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी.

कन्या- दूसरों के सुझावों को दिल से स्वीकार करेंगे, लाभ की संभावना बनेगी. नौकरी एवं राजकीय कार्य में सफ्लता मिलेगी.

तुला- उलझे मामले चतुराई से सुलझा लेंगे. जरूरतमंदों की मदद करके खुशी मिलेगी. प्रिय व्यक्ति से मानसिक पीड़ा होगी. लाभ कम व्यय की अधिकता रहेगी.

वृश्चिक- झूठ बोलकर अपना नुकसान कर लेंगे. मेहमानों की आवाजाही बनी रहेगी. कार्यो में व्यस्तता रहेगी. आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा.

धनु- आलोचना से घबराने की बजाये, डटकर मुकाबला करें. नुकसान से बच सकते हैं. मन में शांति और संतोष बना रहेगा. आय के मार्ग प्रशस्त होंगे.

मकर- लगातार नुकसान से आत्मविश्वास कमजोर पड़ सकता है, नये संपर्को से लाभ होगा. शत्रुओं पर आपका प्रभाव रहेगा. लाभ संचित होगा. कोई बात मालुम होगी.

कुम्भ- सपने साकार करने के लिये मेहनत बढ़ाना आवश्यक है. विवादों से दूर रहें. मन में विशेष प्रसन्नता रहेगी. अतिथि वृषभमन का योग है.

मीन- युवाओं को कैरियर की चिन्ता रहेगी. तनाव की स्थिति में फैसला लेना मुश्किल है. पराक्रम में वृद्धि होगी. नौकर चाकर एवं अधिनस्थ का सहयोग रहेगा.

SUDOKU 7479

				5	1	4		
			7				2	
		8						3
	1							8
5				4				9
7							6	
4						7		
	2				6			
		3	9	8				

• प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. • पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. • पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7478

4	7	6	3	5	2	9	1	8
5	9	8	6	7	1	4	3	2
2	3	1	8	9	4	7	6	5
6	8	5	7	3	9	2	4	1
3	2	4	5	1	6	8	7	9
7	1	9	4	2	8	3	5	6
8	4	3	2	6	5	1	9	7
1	5	2	9	4	7	6	8	3
9	6	7	1	8	3	5	2	4